जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 287 प्रभात बीकानेर, मंगलवार 12 मई, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

## क्या प्र.मंत्री मोदी की अपील अर्थव्यवस्था के ''टिपिंग पॉइन्ट'' पर पहुँचने का संकेत है?

### जापान की वित्तीय फर्म नोमूरा होल्डिंग्स ने मोदी की अपील के विश्लेषण में यह आशंका जताई

- नोमूरा होल्डिंग्स ने प्र.मंत्री मोदी की अपील को मद्देनज़र उन नीतिगत कदमों की पहचान की है, जिन्हें नई दिल्ली आने वाले दिनों में उठा सकती है। उसने विदेशी मुद्रा रिज़र्व संग्रह योजना शुरु किए जाने की संभावना व्यक्त की।
- नोमूरा ने पैट्रोल और डीज़ल की कीमतों में दस प्रतिशत वृद्धि की बात की और बताया कि सरकारी तेल कंपनियों को इस समय प्रतिमाह 30,000 करोड़ रूपए का नुकसान हो रहा है।
- विपक्षी दलों ने मोदी की अपील की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा, यह अपील सरकार की असफलता का प्रमाण है, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने प्र.मंत्री की विदेश यात्रा पर और चुनाव प्रचार में भारी खर्च पर निशाना साधा और लिखा ''राजा मस्त जनता त्रस्त''।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मई। राज्य चुनावों के परिणाम आने के तुरंत बाद आर्थिक मितव्ययिता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई सात सूत्रीय अपील की विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की है, वहीं जापानी वित्तीय फर्म नोमुरा होल्डिंग्स ने उन नीतिगत कदमों की पहचान की है, जिन्हें नई दिल्ली आगामी हफ्तों में शुरू कर सकती है। नोमुरा के अनुसार, इन कदमों में सोना सहित, गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करना और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एनआरएस) के तहत नियमों को कड़ा करना शामिल हो सकता है। वर्तमान में भारतीयों को वार्षिक 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक विदेश भेजने की अनुमति है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि भारत सरकार रुपया मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा जमा संग्रह योजना शुरू करने पर भी विचार कर सकती है।

नोमुरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नागरिकों से अनावश्यक खर्च को कम करने और पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा संरक्षण की अपील यह संकेत देती है कि भारत की वित्तीय स्थिति ''टिपिंग पॉइंट'' पर पहुंच सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के बयान यह दर्शाते हैं कि सरकार ने जो समायोजन किया है, उसका भार धीरे-धीरे परिवारों से साझा करने की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव भारत के वित्तीय संतुलन पर दबाव डाल रहे हैं।

नोमुरा ने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियां वर्तमान में ईंधन और एलपीजी की बिक्री पर प्रति माह 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही हैं। नोमुरा का अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से भारत में मुद्रास्फीति में लगभग 0.5 प्रतिशत पॉइन्ट्स की वृद्धि हो सकती है।

इस बीच, विपक्षी नेताओं ने आयात

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी को जेल भेजा

- घोटाले में दलाल की भूमिका निभाने वाला संजय बडाया 13 मई तक पुलिस रिमांड पर।

जयपुर, 11 मई। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं, अदालत ने मामले में दलाल की भूमिका निभाने वाले संजय बड़ाया को 13 मई तक पुलिस रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है।

रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एसीबी की ओर से पूर्व मंत्री महेश जोशी को विशेष अदालत में पेश किया गया। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शालिनी ने आरोपी की पुलिस अभिरक्षा की अवधि को बढ़ाने की गुहार की, जिसका महेश जोशी की ओर से विरोध किया गया। वहीं एसीबी की ओर से हाल ही में गिरफ्तार संजय बड़ाया को अदालत में पेश कर पांच दिन का रिमांड मांगा गया। एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी बड़ाया से मामले को लेकर पूछताछ करनी है। ऐसे में उसे पांच दिन के रिमांड पर सौंपा जाए। इस पर अदालत ने बड़ाया को 13 मई तक पुलिस रिमांड पर एसीबी को

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## केरल में कांग्रेस के सहयोगी दलों की राय सतीशन के पक्ष में है

### राहुल गांधी वेणुगोपाल के पक्ष में हैं, पर अगर उनकी नहीं चली तो वे वेणुगोपाल को कोई और बड़ा पद दे सकते हैं, शायद पार्टी अध्यक्ष का पद

- सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल अगले वर्ष समाप्त होने वाला है।
- केरल में जहाँ अधिकांश विधायकों की पसंद वेणुगोपाल हैं, वहीं जनता की पसंद सतीशन हैं, उनके लिए आम कार्यकर्ता राज्य भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस हाईकमान ने भारी नाराज़गी भी जताई।
- केरल में कांग्रेस नेतृत्व भारी दुविधा में हैं, इसलिए अब चयन प्रक्रिया में सोनिया गांधी, ए के एंटनी व सहयोगी दलों को शामिल करने पर भी विचार चल रहा है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मई। केरल में चुनाव परिणाम घोषित होने के लगभग एक सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। इसका कारण कांग्रेस के अंदर मौन खींच-तान है, जिसमें शीर्ष पद के लिए चार उम्मीदवार मैदान में हैं। सूची में सबसे आगे पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, इसके बाद वी.डी. सतीशन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चैन्नितला हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन भी खुद को दावेदार मान रहे हैं।

पार्टी अभी भी परामर्श प्रक्रिया में है, जो दो वरिष्ठ नेताओं, अजय माकन और मुकुल वासनिक, के राज्य में निरीक्षक के रूप में भेजते ही शुरु हो गई थी।

उनकी रिपोर्टों के अनुसार, जो उन्होंने विधायकों और पार्टी के स्थानीय नेताओं से परामर्श के बाद सौंपी हैं, अधिकांश विधायक वेणुगोपाल के पक्ष में हैं, जो वरिष्ठ पार्टी नेता राहुल गांधी की पसंद भी हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति के वी.डी. सतीशन, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, की ओर से उनका कड़ा विरोध किया जा रहा है।

जहां केसी वेणुगोपाल विधायकों की पसंद माने जा रहे हैं, वहीं वी.डी. सतीशन जनता की पसंद प्रतीत हो रहे हैं। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ता सतीशन के समर्थन में रैलियाँ निकाल रहे हैं। केन्द्रीय नेता इससे नाराज़ हैं तथा उन्होंने सतीशन को ऐसे प्रदर्शन बंद करवाने का निर्देश दिया।

और भी जटिलताएँ हैं। केरल की 140-सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतीं, लेकिन इनमें से सभी कांग्रेस के पास नहीं गईं।

कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के पास 22 सीटें हैं। शेष सीटें अन्य घटक दलों ने जीती हैं। इसलिए आईयूएमएल की राय का

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## 'हाईकोर्ट्स जमानत याचिकाओं को प्राथमिकता दें'

### सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए दिशा निर्देश जारी किये

- सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बैंच ने इलाहाबाद व पटना हाईकोर्ट का विशेष रूप से हवाला दिया और कहा, इन हाईकोर्ट्स में जमानत याचिकाओं के लंबित मामले बड़ी समस्या हैं, जब कि यहाँ जज एक दिन में कई केस निपटाते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लंबित जमानत याचिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक आधार पर सूचीबद्ध की जाएं। नई याचिका को दायर होने के बाद ''ऑल्टरनैट डे'' पर या एक सप्ताह के भीतर सूचीबद्ध किया जाए।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 मई। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के उच्च न्यायालयों को जमानत याचिकाओं के त्वरित रूप से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए, और जमानत मामलों में लंबित मामलों और सुनवाई में देरी पर चिंता जताई।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों की सुनवाई में देरी कई न्यायक्षेत्रों में गंभीर समस्या बनी हुई है, विशेष रूप से इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालयों में।

पीठ ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ आलोचना के लिए नहीं हैं, बल्कि न्यायिक दक्षता बढ़ाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से हैं।

सर्वोच्च न्यायालय उस मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने पहले सभी उच्च न्यायालयों से लंबित जमानत याचिकाओं के विवरण मांगे थे। जबकि अधिकांश उच्च न्यायालयों ने डेटा प्रदान किया और समय पर सुनवाई के लिए कदम उठाए, पीठ ने कुछ अदालतों में चिंताजनक रूप से लंबित मामलों का उल्लेख किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विशेष रूप से हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है, हालांकि न्यायाधीश एक दिन में सैकड़ों मामलों की सुनवाई करते हों।

प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे जमानत याचिकाओं को साप्ताहिक या पाक्षिक

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## सोमनाथ के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर कुंभाभिषेक

- विशेष क्रेन की सहायता से प्रधानमंत्री ने 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया।

सोमनाथ/अहमदाबाद, 11 मई। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर सोमवार को ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बना, जब मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर पहली बार कुंभाभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष क्रेन की सहायता से 11 पवित्र तीर्थों के जल से मंदिर शिखर का कुंभाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में भगवान सोमनाथ महादेव का जलाभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टरों से मंदिर परिसर में पुष्पवर्षा की गई। भारतीय वायुसेना

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ईरान ने होर्मुज़ में टोल वसूली के नियम घोषित किए

### ईरान के मीडिया ने कहा, ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट पर पूर्ण प्रभुसत्ता हासिल करने की व्यवस्था तैयार की ली है

- पर्शियन गल्फ सॉवरिन अथॉरिटी के नए नियमों के अनुसार, जो जहाज़ होर्मुज़ से गुजरना चाहते हैं, उन्हें पहले फॉर्म भर कर ई-मेल करना होगा, उसके बाद उनका आवेदन प्रौसेस होगा, फिर आगे के निर्देश मेल द्वारा दिए जाएंगे।
- नियमों के अनुसार, गलत या अधूरी जानकारी देने का खामियाजा आवेदनकर्ता को भुगतना पड़ेगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मई। मध्य पूर्व में युद्ध को समाप्त करने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान की नाकाबंदी के बीच, एक शिपिंग जर्नल (पत्रिका) के अनुसार, तेहरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू किए हैं और उनसे टोल वसूलने का निर्णय लिया है।

स्ट्रेट पर नियंत्रण को औपचारिक बनाने का कदम ऐसे समय पर उठाया गया, जब अमेरिका इस पतले रास्ते को फिर से खालेने के लिए एक डील पर जोर दे रहा था, जिसके माध्यम से सामान्यतः दुनिया के 20 प्रतिशल तेल का परिवहन होता है।

शिपिंग और समुद्री व्यापार पर खबरें और जानकारी देने वाले, इस उद्योग के जर्नल लॉयड्स लिस्ट ने कहा, "फारस की खाड़ी स्ट्रेट अथॉरिटी ने पहले ही एक नया फ्रेम वर्क शुरु कर दिया है, जिसके तहत जहाजों को ट्रांज़िट ऑथराइजेशन प्राप्त करने और यात्रा से पहले टोल का भुगतान करना आवश्यक है।"

जर्नल ने "वैसल इन्फॉर्मेशन डैक्लरेशन" नाम के एक फॉर्म का हवाला दिया, जिसे अथॉरिटी द्वारा भेजा गया, और कहा कि स्ट्रेट से सुरक्षित मार्ग चाहने वाले सभी जहाजों को "मालिकाना हक, बीमा, चालक दल के विवरण और निर्धारित ट्रांज़िट मार्ग सहित, विस्तृत रिकॉर्ड जमा कराने होंगे।"

रिपोर्ट के अनुसार, इस फ़ॉर्म में 40 से अधिक प्रश्न हैं, जिनमें जहाज का नाम, पहचान संख्या, पूर्व नाम, मूल और गंतव्य देश, जहाज के पंजीकृत मालिकों, ऑपरेटरों और चालक दल की राष्ट्रीयता, साथ ही जहाज पर मौजूद माल का विवरण भी बताना होगा।

अंग्रेज़ी भाषी प्रसारणकर्ता ईरानी प्रेस टीवी ने यह भी बताया कि तेहरान ने "स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर संप्रभुता का अभ्यास करने के लिए एक प्रणाली बनाई है" और स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईमेल से "नियम" भेजे जा रहे हैं।

पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (पी.जी.एस.ए.) के अनुसार, यह फ़ॉर्म "पूर्ण और सटीक जानकारी" के साथ भरा जाना चाहिए और जहाजों के स्ट्रेट से गुजरने से पहले अथॉरिटी को ईमेल किया जाना चाहिए। उसने कहा कि ट्रांज़िट अनुरोधों को संधारित करने के बाद, "अग्रिम निर्देश ईमेल के माध्यम से जहाजों को भेजे जाएंगे।"

इसमें यह भी चेतावनी दी गई कि किसी भी गलत या अधूरी जानकारी के लिए पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## टीवीके विधायक प्रभाकर तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे

- नामांकन के अंतिम दिन तक केवल उनका नामांकन पत्र दाखिल हुआ।

चेन्नई, 11 मई। तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद पर तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के विधायक जेसीडी प्रभाकर का निर्विरोध निर्वाचन तय है। विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सोमवार को सिर्फ प्रभाकर ने नामांकन किया। इस कारण उनके निर्विरोध निर्वाचन की सिर्फ घोषणा बाकी है।

सत्तारूढ़ टीवीके के मुताबिक, विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की घोषणा मंगलवार को आधिकारिक रूप से की जाएगी, जिसके बाद वे सदन की

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## शुभेन्दु अधिकारी के पीए के हत्यारों के महत्वपूर्ण सुराग मिले, तीन संदिग्ध गिरफ्तार

### बहुत बारीकी से बनाई गई योजना का सुराग ढूंढने में पुलिस को आधुनिक तकनीक से भारी मदद मिली

- पुलिस ने हत्या स्थल पर दिखी कार की जानकारी जुटानी शुरु की तो एक सीसीटीवी फुटेज में वह कार टोल प्लाजा पर दिखी, पुष्टि होने पर आगे जाँच की तो पता लगा कि कार ने यूपीआई से टोल भुगतान किया है।
- यूपीआई भुगतान स्लिप से फोन नम्बर की जानकारी मिली और फोन नम्बर के आधार पर पुलिस को एक वॉट्सऐप ग्रुप को पकड़ने में सफलता मिली। इसी आधार पर पुलिस को यूपी, बिहार व झारखंड की लोकेशन का भी पता चला।
- समझा जाता है कि यह हत्या मोटी रकम के एवज में की गई थी, पर वह पैसा कौन दे रहा था और क्यों? क्या साजिशकर्ता को यकीन था तृणमूल की वापसी होगी और मामला दब जाएगा या फिर वह उच्च स्तर पर कोई संदेश देना चाहता है, यह भारी जाँच का मुद्दा है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मई। सोच समझकर योजना बनाकर की गई हत्याओं के मामलों को सुलझाना अब बहुत मुश्किल नहीं रह गया है और कातिलों को यह भी नहीं पता होता कि उन्होंने अपने निशान कहाँ छोड़े और किस रूप में छोड़े। पुलिस ने शुभेन्दु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में कम से कम तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर हत्या करने वाले गिरोह का हिस्सा होने का संदेह है।

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के व्यक्तिगत सहायक की हत्या के अपराधियों की शुरुआत में पकड़ मुश्किल लग रही थी, और उनके पकड़े जाने और सजा दिलाने की उम्मीदें बहुत कम थीं।

हत्या के मामले में हर मिनट तक की योजना बनाई गई थी और योजना का निष्पादन भी बिल्कुल सही था, जिससे जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यह पेशेवर हत्यारे गिरोह का काम है। अपराधियों ने घटना स्थल पर अपनी पहचान का कोई सुराग नहीं छोड़ा, जिससे जांचकर्ताओं को थोड़े समय के लिए भ्रमित भी होना पड़ा।

राज्य भर में कई स्थानों पर सघन जांच अभियान के बाद, पुलिस को कोलकाता के पास एक टोल प्लाजा के लेनदेन से एक अहम सुराग मिला। हत्या स्थल पर देखी गई कार को टोल प्लाजा से गुजरते देखा गया, और विस्तृत सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण ने पुष्टि की कि यह वही कार थी।

इसके बाद जांचकर्ताओं ने टोल गेट रिकॉर्ड्स को देखा और देखा कि टोल भुगतान, जो नेटवर्क के माध्यम से किए गए थे, में वह फोन नंबर जुड़ा था, जिससे भुगतान हुआ था। एक बार इस मुख्य सुराग की पुष्टि हो जाने के बाद बाकी की खोज आसान हो गई।

जांच के दौरान, टीम यूपी, बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों और पतों तक पहुंची। टेलीफोन नंबर और सीसीटीवी फुटेज ने बाद में हत्या गैंग के सदस्यों को जोड़ने और उनके वॉट्सऐप ग्रुप को क्रैक करने में मदद की।

अब, जब जांचकर्ताओं को इस बात का अच्छा अंदाजा हो गया है कि कौन-कौन इस अपराध में शामिल हो सकता है, तो गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी ज्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन हत्यारों को किसी प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के कार्यकारी सहायक को मारने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय इसके कि उन्होंने मोटी रकम पहले से तय कर रखी थी।

असल सवाल यह है कि आखिरकार इस हत्या को अंजाम देने के लिए हत्यारों को किसने हायर किया। हत्या की योजना बंगाल चुनावों से पहले ही बनाई गई होगी। यह केवल चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही हुई। यह वह समय था जो चुनाव और परिणाम के बीच का अंतर प्रदान करता था।

जिन लोगों ने हत्या का आदेश दिया, उन्होंने निश्चित रूप से यह उम्मीद

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## शुभेन्दु के पीए के हत्याकांड में बलिया निवासी गिरफ्तार

- प. बंगाल पुलिस ने राजसिंह को लखनऊ से लौटते समय पकड़ा।

बलिया, 11 मई। बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के पीए हत्याकांड के तार बलिया से भी जुड़े हैं। इस बहुचर्चित हत्याकांड में गड़वार थाना क्षेत्र के कुरेजी के मूल निवासी राज सिंह की गिरफ्तारी से जिलेवासी सन्न हैं।

पुलिस के मुताबिक, पश्चिम बंगाल पुलिस ने रविवार की देर रात बलिया निवासी राज सिंह को लखनऊ से लौटते समय अयोध्या से गिरफ्तार किया है। वे लखनऊ में आयोजित एक शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे। राज सिंह के बलिया सदर कोतवाली के आनंद नगर मोहल्ले स्थित आवास पर ताला लटक रहा है। आसपास के लोगों की मानें तो उसके परिजन दूसरी जगह चले गए हैं।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )